



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20092023-248833
CG-DL-E-20092023-248833

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 222]
No. 222]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 19, 2023/भाद्र 28, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 19, 2023/BHADRA 28, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2023

मामला संख्या: एडी (एसएसआर) - 05/2023

विषय: मलेशिया में मूलतः अथवा वहां से निर्यातित 'टेम्पर्ड कोटेड और अनकोटेड ग्लास' के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा. सं. 07/11/2023-डीजीटीआर.—मैसर्स बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड (इसके बाद 'आवेदकों' के रूप में संदर्भित) द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) और सीमा शुल्क टैरिफ (डंप किए गए लेखों पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी की पहचान, मूल्यांकन और संग्रह और 1995, समय-समय पर संशोधित (इसके बाद 'एडी नियम' के रूप में संदर्भित), के अनुसार मलेशिया (बाद में 'संबद्ध देश के रूप में संदर्भित) में उत्पन्न होने वाले या वहां से निर्यात किए गए टेक्सचर्ड टेम्पर्ड कोटेड और अनकोटेड ग्लास (बाद में 'विषय वस्तुओं' के रूप में संदर्भित किया जाता है) के आयात पर लगाए गए एंटी-डंपिंग शुल्क को जारी रखने के लिए सूर्यास्त समीक्षा शुरू करने की मांग की गई है।

2. अधिनियम की धारा 9ए(5) और एडी नियमों के नियम 23(1बी) के अनुसार, लगाए गए पाटन रोधी शुल्क, जब तक कि पहले रद्द नहीं किया जाता, ऐसी तारीख से पांच साल की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। प्राधिकरण को पाटन रोधी शुल्क जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने और यह आकलन करने की आवश्यकता है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। उसी के अनुसार, प्राधिकरण को घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करने की आवश्यकता है कि क्या पाटन रोधी शुल्क लगाने की आवश्यकता है, और क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

क. पृष्ठभूमि

3. मलेशिया से विषय वस्तुओं के आयात से संबंधित मूल जांच प्राधिकरण द्वारा दिनांक 05.02.2018 की अधिसूचना संख्या 6/45/2017-डीजीएडी के तहत शुरू की गई थी। प्राधिकरण द्वारा दिनांक 17.01.2019 की अधिसूचना संख्या 6/45/2017-डीजीएडी के माध्यम से अंतिम निष्कर्ष जारी किए गए थे, जिसमें निश्चित पाटन रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी।
4. उक्त सिफारिश के आधार पर, केंद्र सरकार द्वारा मलेशिया में उत्पन्न या निर्यात किए गए विषय वस्तुओं के आयात पर दिनांक 26.02.2019 की सीमा शुल्क संख्या 12/2019-सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत निश्चित पाटन रोधी शुल्क लगाया गया था। वर्तमान पाटन रोधी शुल्क 25.02.2024 तक लागू हैं।

ख. विचाराधीन उत्पाद

5. विचाराधीन उत्पाद मूल जांच के समान है यानी, "टेक्सचर्ड टेम्पर्ड लेपित और अनकोटेड ग्लास"। मूल जांच के तहत परिभाषित उत्पाद निम्नानुसार था-
"टेक्सचर्ड टफनेड (टेम्पर्ड) ग्लास जिसमें न्यूनतम 90.5% ट्रांसमिशन होता है जिसकी मोटाई 4.2 मिमी (0.2 मिमी की सहनशीलता सहित) से अधिक नहीं होती है और जहां कम से कम एक आयाम 1500 मिमी से अधिक होता है, चाहे लेपित या अनलेपित हो।"
6. वर्तमान जांच एक सूर्यास्त समीक्षा जांच होने के नाते, विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही है जो मूल जांच में परिभाषित किया गया है।
7. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ वर्गीकरण के उपशीर्षक 70071900 के तहत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 70 के तहत वर्गीकृत किया गया है। हालांकि, अतीत में, पीयूसी को अन्य उपशीर्षकों के तहत भी आयात किया गया है, जैसे कि 70031990, 70051010, 70051090, 70052190, 70052990, 70053090, 70071900, 70072190, 70072900, 70169000, 70200090 और 85414011। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है, और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है क्योंकि प्रस्तावित पीयूसी को अन्य एचएस कोड के तहत आयात किया जा सकता है।
8. वर्तमान जांच के पक्षकार पीयूसी पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं और प्राधिकरण के समक्ष दायर आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण के प्रसार के 15 दिनों के भीतर पीसीएन, यदि कोई हो, का प्रस्ताव कर सकते हैं, जैसा कि इस जांच शुरूआत अधिसूचना के पैराग्राफ 27 में दर्शाया गया है।

ग. समान वस्तु

9. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित और विषय देश से निर्यात की जाने वाली विषय वस्तुओं में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है और दोनों लेख की तरह हैं। आवेदक द्वारा निर्मित और विषय देश से आयातित उत्पाद भौतिक रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया प्रौद्योगिकी, कार्यों के उपयोग, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण विपणन और माल के टैरिफ वर्गीकरण जैसे आवश्यक उत्पाद विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। उपभोक्ता दोनों का उपयोग कर सकते हैं और परस्पर उपयोग कर रहे हैं। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से सहायक हैं, और इसलिए, नियमों के तहत 'अनुच्छेद की तरह' माना जाना चाहिए। इसलिए, वर्तमान जांच के

उद्देश्य से, भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित विषय वस्तुओं को विषय देश से आयात की जा रही विषय वस्तुओं के लिए 'लेख की तरह' माना जा रहा है।

घ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

10. सूर्यास्त समीक्षा जांच के लिए आवेदन मेसर्स बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है, जो भारत में विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है। प्राधिकरण नोट करता है कि आवेदक भारत में कुल घरेलू उत्पादन का 100% हिस्सा रखता है और प्रस्तुत किया है कि उसने न तो विषय देश से विषय वस्तुओं का आयात किया है और न ही यह भारत में विषय वस्तुओं के किसी आयातक या विषय देश में विषय वस्तुओं के किसी निर्यातक या उत्पादक से संबंधित है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण नोट करता है कि आवेदक नियमों के नियम 2 (बी) के अर्थ के भीतर एक पात्र 'घरेलू उद्योग' का गठन करता है और आवेदन नियमों के नियम 5 (3) के संदर्भ में खड़े होने के मानदंडों को पूरा करता है।

ड. संबद्ध देश

11. वर्तमान समीक्षा जांच में विषय देश मलेशिया है।

च. जांच की अवधि

12. वर्तमान सूर्यास्त समीक्षा जांच के लिए प्रस्तावित जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल 2022 से मार्च 2023 (12 महीने) और 2019-20, 2020-21 2021-22 यानी क्षति जांच अवधि के तुरंत पहले तीन साल है। यह ध्यान दिया जाता है कि प्रस्तावित अवधि आवेदक के प्रदर्शन की सबसे हालिया अवधि है। तदनुसार, जांच की जाने वाली प्रस्तावित क्षति की अवधि 1 अप्रैल 2019 - 31 मार्च 2020, 1 अप्रैल 2020 - 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 - 31 मार्च 2022 और पीओआई है।

छ. प्रक्रिया

13. सूर्यास्त समीक्षा जांच में 17.01.2019 की अधिसूचना संख्या 6/45/2017-डीजीएडी द्वारा प्रकाशित अंतिम निष्कर्षों के सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा, जिसमें मलेशिया में उत्पन्न होने वाली या निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के आयात पर पाटन रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई है।
14. नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान इस समीक्षा में यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

ज. पाटन की निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना

सामान्य मान

15. विषय देश यानी, मलेशिया एक बाजार अर्थव्यवस्था है, और इसलिए विषय वस्तुओं का सामान्य मूल्य उनके द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर आधारित होगा।
16. तथापि, वर्तमान समीक्षा जांच शुरू करने के उद्देश्य से उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत के साथ-साथ प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागतों के लिए उचित वृद्धि और नियमों के अनुसार निर्धारित लाभो के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण किया गया है।

निर्यात कीमत

17. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस) से प्राप्त लेनदेन-वार आयात आंकड़ों के आधार पर संबंधित वस्तुओं के निर्यात मूल्य की गणना की गई है। पूर्व-फैक्टरी स्तरों पर कीमतों को बनाने के लिए उचित मूल्य समायोजन किए गए हैं ताकि वे सामान्य मूल्य के साथ तुलनीय हो जाएं।

पाटन मार्जिन

18. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना एक्स-फैक्ट्री स्तर पर की गई है, जो प्रथम दृष्टया स्थापित करता है कि डंपिंग मार्जिन डी मिनिमिस स्तर से ऊपर है और संबंधित देश से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबंधित देश से विचाराधीन उत्पाद को संबंधित देश के निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में डंप किया जा रहा है।

इ. क्षति और कारणात्मक संबंध

19. विषय देश से विषय वस्तुओं के आयात पर पाटन रोधी शुल्क के अस्तित्व के बावजूद विषय देश से विषय वस्तुओं के आयात की मात्रा अधिक बनी हुई है। इसे ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन या क्षति की पुनरावृत्ति की प्रथम दृष्टया संभावना की जांच की है। प्राधिकरण ने आवेदन में लगाए गए आधारों के आधार पर प्रथम दृष्टया मौजूदा कर्तव्यों को जारी रखने की भी जांच की है।
20. आवेदक ने दावा किया है कि जबकि घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति नहीं लगी है, अन्य देशों से गैर-पारिश्रमिक डंप और सब्सिडी वाले आयात ने वसूली प्रक्रिया को रोक दिया है, और इसलिए पाटन रोधी शुल्कों को बंद करने और जारी रखने से घरेलू उद्योग को नुकसान होने की संभावना है। इसके अलावा, आवेदक ने सकारात्मक पाटन और क्षति मार्जिन, पाटन का इतिहास, विषय देश में उपलब्ध क्षमता और क्षमता विस्तार, विषय देश में घरेलू मांग की कमी, और शुल्क की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग पर पाटन की पुनरावृत्ति के संभावित प्रभाव जैसे कारकों के आधार पर क्षति की संभावना का दावा किया है। पाटन रोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में पाटन की संभावना और घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचने के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।

ज. सूर्यास्त समीक्षा जांच की शुरुआत

21. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर, और आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर जो पाटन और घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचने की संभावना को प्रमाणित करते हैं, और नियमों के नियम 23 (1 बी) के अनुसार, प्राधिकरण विषय वस्तुओं के संबंध में लागू शुल्कों को निरंतर लागू करने की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए वर्तमान जांच शुरू करता है। संबंधित देश में उत्पन्न या निर्यात किया गया, और यह जांच करना कि क्या मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना है और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को नुकसान होने की संभावना है।

ट. सूचना प्रस्तुत करना

22. निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे जाने वाले सभी पत्र ई-मेल पत्तों dd11-dgtr@gov.in और dd16-dgtr@gov.in पर तथा उनकी एक प्रति adg14-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in को भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
23. संबंधित देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबंधित देश की सरकार और भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं, जो विषय वस्तुओं से जुड़े होने के लिए जाने जाते हैं, को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सभी प्रासंगिक जानकारी दर्ज कर सकें। ऐसी सभी जानकारी इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकरण द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित फॉर्म और तरीके से दायर की जानी चाहिए।
24. कोई अन्य इच्छुक पक्षकार भी इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकरण द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिसों द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से इस दीक्षा अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संबंधित एक प्रस्तुति दे सकता है।
25. प्राधिकरण के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुति देने वाले किसी भी पक्ष को अन्य इच्छुक पक्षों को इसका एक गैर-गोपनीय संस्करण उपलब्ध कराना आवश्यक है।

26. इच्छुक पार्टियों को आगे निर्देशित किया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (<https://www.dgtr.gov.in/>) को नियमित रूप से देखते रहें और जानकारी के साथ-साथ आगे की जाँच पड़ताल प्रक्रियाओं से अवगत रहें।

ठ. समय सीमा

27. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पतों dd11-dgtr@gov.in और dd16-dgtr@gov.in तथा adg14-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in को एक प्रति के साथ प्राधिकारी द्वारा आवेदक के आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण को परिचालित किए जाने अथवा एडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर इमेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी एडी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
28. सभी इच्छुक पार्टियों को सलाह दी जाती है कि वे तत्काल मामले में अपनी रुचि (हित की प्रकृति सहित) बताएं और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली के जवाब दाखिल करें।
29. जहां कोई इच्छुक पक्ष प्रस्तुतियाँ दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है, उसे एडी नियम, 1995 के नियम 6(4) के संदर्भ में ऐसे विस्तार के लिए पर्याप्त कारण प्रदर्शित करना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर आना चाहिए।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

30. जहां वर्तमान में कोई पक्षकार गोपनीय अनुरोध करता है या प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर सूचना देता है, वहां उसे एडी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी की गई संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
31. ऐसे अनुरोध पर प्रत्येक पृष्ठ पर 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी को किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा और प्राधिकारी को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने की स्वतंत्रता होगी।
32. गोपनीय संस्करण में वह सभी जानकारी शामिल होगी जो प्रकृति से, गोपनीय और / या अन्य जानकारी है, जिसे ऐसी जानकारी का आपूर्तिकर्ता गोपनीय के रूप में दावा करता है। ऐसी जानकारी के लिए जिसे प्रकृति से गोपनीय होने का दावा किया जाता है, या जिस जानकारी पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, सूचना के आपूर्तिकर्ता को प्रदान की गई जानकारी के साथ एक अच्छा कारण विवरण प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी जानकारी का खुलासा क्यों नहीं किया जा सकता है।
33. हितबद्धपक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश को अनिवार्य रूप से गोपनीय अंश की अनुकृति होना चाहिए जिसमें "गोपनीय सूचना" अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो) होनी चाहिए और ऐसी सूचना को जिस सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है, उस पर निर्भर रहते हुए उचित और पर्याप्त रूप से सारांशीकृत होना चाहिए।
34. अगोपनीयसारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की पर्याप्त तर्कसंगत समझ बन सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय आधार पर सूचना देने वाला पक्षकार इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के स्तर तक एडी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसे कारणों को पर्याप्त और पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाला एक विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
35. इच्छुक पक्ष इस जांच शुरूआत अधिसूचना के पैराग्राफ 27 में दर्शाए गए आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण के संचलन की तारीख से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

36. सार्थक अगोपनीय अंश के बिना किया गया कोई अनुरोध या एडी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार गोपनीय दावे संबंधी किसी अनुरोध को पर्याप्त और पूरे कारणों के विवरण के बिना प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
37. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक है या यदि जानकारी का आपूर्तिकर्ता या तो जानकारी को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी जानकारी की अवहेलना कर सकता है।
38. प्रदान की गई जानकारी की गोपनीयता की आवश्यकता को संतुष्ट होने और स्वीकार करने पर प्राधिकारी ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्ष के विशिष्ट प्राधिकरण के बिना किसी भी पक्ष को इसका खुलासा नहीं करेगा।
39. पंजीकृत इच्छुक दलों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जिसमें उन सभी को अनुरोध किया जाएगा कि वे अपनी प्रस्तुतियों के गैर-गोपनीय संस्करण और अन्य जानकारी को अन्य सभी इच्छुक पक्षों को ईमेल करें।

ढ. असहयोग

40. यदि कोई इच्छुक पक्ष इस प्रारंभिक अधिसूचना में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय के भीतर या उचित अवधि के भीतर या अन्यथा आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है, या बाद में अलग-अलग संचार के माध्यम से प्रदान की गई समय अवधि में आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है, या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकरण ऐसे इच्छुक पक्ष को गैर-सहयोगी घोषित कर सकता है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड कर सकता है और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है। जैसा कि यह उचित लगता है।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2023

Case No. AD - SSR (05/2023)

Subject: Initiation of Sunset Review Investigation concerning imports of “Textured Tempered Coated and Uncoated Glass” originating in or exported from Malaysia.

F. No. 07/11/2023-DGTR.—M/s Borosil Renewables Limited (hereinafter referred to as the ‘applicant’), has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the ‘Authority’), on behalf of domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the ‘Act’) and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Rules’), seeking initiation of a sunset review investigation for continued imposition of anti-dumping duties levied on imports of “Textured Tempered Coated and Uncoated Glass” (hereinafter referred to as the ‘subject goods’), originating in or exported from Malaysia (hereinafter referred to as the “subject country”).

2. In terms of Section 9A (5) of the Act and Rule 23 (1B) of the AD Rules, the anti-dumping duties imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review the need for the continued imposition of the anti-dumping duties, and to assess whether the expiry of the duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the same, the Authority is required to review, on the basis of duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry as to whether there is a need for the continued imposition of the anti-dumping duty, and whether the expiry of the duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

A. Background

3. The original investigation concerning imports of the subject goods from Malaysia was initiated by the Authority vide Notification No.6/45/2017-DGAD dated 05.02.2018. The Final Findings was issued by the Authority vide Notification No. 6/45/2017-DGAD dated 17.01.2019, recommending the imposition of definitive anti-dumping duties.
4. On the basis of the said recommendation, definitive anti-dumping duties were imposed by the Central Government vide Custom Notification No.12/2019-Customs (ADD) dated 26.02.2019 on the imports of the subject goods, originating in or exported from Malaysia. The current anti-dumping duties are in force up to 25.02.2024.

B. Product under Consideration

5. The product under consideration is the same as in the original investigation i.e., “Textured Tempered Coated and Uncoated Glass”. The product defined under the original investigation was as follows-
“Textured Toughened (Tempered) Glass with a minimum of 90.5% transmission having thickness not exceeding 4.2 mm (including tolerance of 0.2 mm) and where at least one dimension exceeds 1500 mm, whether coated or uncoated”.
6. The present investigation being a sunset review investigation, the scope of the product under consideration remains the same as defined in the original investigation.
7. The product under consideration is classified under Chapter 70 of the Customs Tariff Act, 1975 under subheading 70071900 of the Customs Tariff Classification. However, in the past, the PUC has also been imported under other sub-headings as well, such as 70031990, 70051010, 70051090, 70052190, 70052990, 70053090, 70071900, 70072190, 70072900, 70169000, 70200090 and 85414011. The customs classification is indicative only, and not binding on the scope of product under consideration since the proposed PUC may be imported under other HS Codes.
8. The parties to the present investigation may provide their comments on the PUC and propose PCNs, if any, within 15 days of circulation of the non-confidential version of the application filed before the Authority as indicated in paragraph 27 of this initiation notification.

C. Like Article

9. The applicant has submitted that there are no significant differences in the subject goods produced by the applicant and exported from the subject country and both are like articles. The product manufactured by the applicant and imported from the subject country are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & usage, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and have been using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable, and hence, should be treated as ‘like article’ under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant in India are being treated as ‘like article’ to the subject goods being imported from the subject country.

D. Domestic Industry & Standing

10. The application for the sunset review investigation has been filed by M/s Borosil Renewables Limited, which is the sole producer of the product under consideration in India. The Authority notes that the applicant holds 100% share of the total domestic production in India and has submitted that it has neither imported the subject goods from the subject country nor is it related to any importer of the subject goods in India or any exporter or producer of the subject goods in the subject country. In view of the above, the Authority notes that the applicant constitutes an eligible ‘domestic industry’ within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

E. Subject Country

11. The subject country in the present review investigation is Malaysia.

F. Period of Investigation

12. The period of investigation (POI) proposed for the present sunset review investigation is from April 2022 to March 2023 (12 months) and 2019-20, 2020-21 & 2021-22 i.e., the immediately preceding three years as the injury investigation period. It is noted that the period proposed is the most recent period of the applicant’s performance. Accordingly, the injury period proposed to be examined is 1st April 2019 - 31st March 2020, 1st April 2020 - 31st March 2021, 1st April 2021 - 31st March 2022, and the POI.

G. Procedure

13. The sunset review investigation will cover all aspects of the final findings published vide Notification No. 6/45/2017-DGAD dated 17.01.2019, recommending the imposition of anti-dumping duty on the imports of subject goods originating in or exported from Malaysia.
14. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, and 20 of the Rules shall be *mutatis mutandis* applicable in this review.

H. Likelihood of Continuation or Recurrence of Dumping**Normal Value**

15. The subject country i.e., Malaysia is a market economy, and hence the normal value of the subject goods will be based on the information provided by them.
16. However, for the purpose of initiation of the present review investigation, the normal value has been constructed based the cost of production of the said article along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules.

Export Price

17. The export price for the subject goods has been computed based on the transaction-wise import data obtained from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI & S). Appropriate price adjustments have been carried out to make the prices at ex-factory levels so that they become comparable with normal value.

Dumping Margin

18. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* establishes that the dumping margin is above the *de minimis* level and is significant with respect to the product under consideration from the subject country. Thus, there is sufficient *prima facie* evidence that the product under consideration from the subject country is being dumped in the domestic market of India by the exporters from the subject country.

I. Likelihood vis-a-vis Injury and Causal Link

19. The quantity of imports of the subject goods from the subject country has remained high despite the existence of anti-dumping duties on the imports of the subject goods from the subject country. In view of the same, the Authority has examined the *prima facie* likelihood of dumping or recurrence of injury in the event of cessation of the existing anti-dumping duty. The Authority has also *prima facie* examined the continuation of existing duties based on the grounds alleged in the application.
20. The applicant has claimed that while the domestic industry has not suffered continued injury, the non-remunerative dumped and subsidized imports from other countries halted the recovery process, and hence cessation and continuation of anti-dumping duties will likely result in injury to the domestic industry. Furthermore, the applicant has claimed the likelihood of injury based on factors such as the positive dumping and injury margins, the history of dumping, capacities available in the subject country and capacity expansion, the lack of domestic demand in the subject country, and the likely impact of recurrence of dumping on the domestic industry in the event of cessation of duties. There is *prima facie* evidence regarding the likelihood of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of anti-dumping duty.

J. Initiation of Sunset Review Investigation

21. On the basis of the duly substantiated application by the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of *prima facie* evidence submitted by the applicant substantiating likelihood of dumping and consequent injury to the domestic industry, and in accordance with Rule 23(1B) of the Rules, the Authority hereby initiates the present investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country, and to examine whether the expiry of existing anti-dumping duty is likely to lead continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry.

K. Submission of Information

22. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses dd11-dgtr@gov.in and ddl6-dgtr@gov.in with a copy to adg14-dgtr@gov.in and adv13-dgtr@gov.in. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
23. The known producers/exporters in the subject country, the Government of the subject country through its Embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the subject

goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.

24. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.
25. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
26. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (<https://www.dgtr.gov.in/>) to stay updated and apprised with the information as well as further processes related to the investigation.

L. Time Limit

27. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at email address dd11-dgtr@gov.in and dd16-dgtr@gov.in with a copy to adg14-dgtr@gov.in and adv13-dgtr@gov.in within 30 days from the date on which the non-confidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Rules.
28. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.
29. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the AD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

M. Submission of Information on Confidential Basis

30. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.
31. Such submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as “non-confidential” information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
32. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
33. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
34. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
35. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the application as indicated in paragraph 27 of this initiation notification.
36. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

37. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
38. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.
39. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions and other information to all other interested parties.

N. Non-Cooperation

40. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification or subsequently time period provided through separate communication, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority